अध्याय 2

राज्य अर्थव्यवस्था

उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे भरोसेमंद पैमाना रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (पहले केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)) सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार कारक लागत और बाजार मूल्यों पर जीडीपी की घोषणा करती रही है। जनवरी 2015 में सीएसओ ने अपने संशोधन में जीडीपी को प्राथमिक मूल्यों पर, सकल मूल्य संवर्धन – जीवीए और बाजार मूल्यों पर जीडीपी के साथ कारक लागत पर प्रतिस्थापित कर दिया, जिसे अब केवल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहा जाता है। यह मध्यवर्ती उपभोग (आउटपुट के आगे उत्पादन में प्रयुक्त और अंतिम उपभोग में प्रयुक्त नहीं) का मूल्य घटा कर अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन का मूल्य है। उत्पादन लागत, प्राथमिक मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर निवल उत्पादन (उत्पादन सब्सिडी को घटा कर उत्पादन कर) कर और निवल उत्पाद करों (उत्पाद सब्सिडी को घटा कर उत्पाद कर) के बीच के अंतर पर आधारित होता है। उत्पादन कर और उत्पादन सब्सिडी का भुगतान या प्राप्ति उत्पादन के संदर्भ में की जाती है और यह भू–राजस्व, स्टैम्प और पंजीकरण शुल्क जैसे उत्पादन आयतन से पृथक होता है। दूसरी तरफ उत्पाद कर और उत्पाद सब्सिडी का भुगतान या प्राप्ति प्रति यूनिट या प्रति उत्पाद किया जाता है, जैसे उत्पाद कर, सेवा कर, जीएसटी, बिक्री कर, निर्यात और आयात शुल्क इत्यादि। कारक लागत में केवल उत्पादन के विभिन्न घटकों को किया गया भुगतान शामिल होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई कर शामिल नहीं होता। बाजार मूल्यों तक पहुंचने के उद्देश्य से हमें कारक लागत में कुल सब्सिडी को घटा कर कुल अप्रत्यक्ष करों को जोड़ना होगा। प्राथमिक मूल्य इनके बीच निर्धारित होता है : इनमें उत्पादन कर (उत्पादन सब्सिडी को घटा कर) शामिल होते हैं लेकिन उत्पाद कर (उत्पाद सब्सिडी को घटा कर) शामिल नही होते। इसलिए मार्केट मूल्य निर्धारित करने के लिए हमें उत्पाद कर (उत्पाद सब्सिडी घटा कर) को प्राथमिक मूल्यों में जोड़ना होता है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय प्राथमिक मूल्यों पर सकल मूल्य संवर्धन–जीवीए जारी करता है। इसलिए इसमें निवल उत्पादन कर शामिल होते हैं, लेकिन निवल उत्पाद कर शामिल नहीं होते। जीडीपी/जीएसडीपी (बाजार मूल्यों पर) के निर्धारण के लिए हमें प्राथमिक मूल्यों पर जीवीए में निवल उत्पाद कर जोड़ने होते हैं।

इसलिए कारक लागत पर जीवीए + निवल उत्पादन कर = प्राथमिक मूल्यों पर जीवीए + निवल उत्पाद कर = मार्किट मूल्य पर जीवीए

1.1 राज्य घरेलू उत्पाद (एसडीपी), किसी राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर किसी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। इसे राज्य की आय भी कहा जाता है। एसडीपी की गणना या आकलन हमेशा मौद्रिक संदर्भ में की जाती है और यह प्रति व्यक्ति आय की गणना में प्रयुक्त होती है। राज्य की आर्थिक समृद्धि के मापन और अर्थव्यवस्था में आ रहे संरचनात्मक बदलाव के अध्ययन के लिए यह संकेतक का काम करता है। एक समयावधि में एसडीपी आकलन आर्थिक विकास के स्तर पर बदलावों की सीमा और दिशा स्पष्ट करता है।

सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन (जीएसवीए) की संरचना अर्थव्यवस्था में किसी समयावधि में विभिन्न सेक्टरों की सापेक्ष स्थिति का अंदाजा उपलब्ध कराती है। जो न केवल अर्थव्यवस्था में हो रहे वास्तविक संरचनात्मक बदलावों को इंगित करता है बल्कि समग्र आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने में भी सहायक होता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली की आय का एक बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र से आता है, जो भारतीय संघ के तेजी से विकसित हो रहे राज्यों के लिए विकास इंजन माना जाता है।

2. अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 का असर

2.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली में कोविड–19 का फैलाव रोकने के लिए सुरक्षित दूरी और पृथकवास उपायों के कड़ाई से पालन के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत दिल्ली महामारी रोग, कोविड–19 विनियमन जारी किया और पूरे रा.रा.क्षे. में सोमवार 23 मार्च 2020 की सुबह 6 बजे से मंगलवार 31 मार्च 2020 की मध्य रात्रि तक लॉकडाउन अधिसूचित किया। इसके बाद 24 मार्च 2020 को 21 दिन का सख्त राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषित किया गया और बाद में इसे बढ़ा कर 31 मई 2020 तक कर दिया गया। भारत ने महामारी के आरंभिक चरण में मार्च से अप्रैल 2020 तक राष्ट्रव्यापी कठोर पूर्णबंदी लागू की। इसके बाद चरणबद्ध रूप से लॉकडाउन में छूट दी गई और रोकथाम उपायों में कुछ ढील दी गई।

2.2 अप्रैल–मई, 2021 में देश में कोविड–19 की दूसरी लहर आई जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मई, 2021 को डेल्टा संक्रमण का नाम दिया और अब भी समूचे विश्व में फैलता जा रहा है। डेल्टा पहले वाले संक्रमणो के मुकाबले तेज़ी से फैलता है और इससे दुनिया में ज़्यादा लोग चपेट में आ रहे हैं और मौतें भी ज्यादा हो रही हैं। दिसंबर, 2021 और जनवरी, 2022 में ओमिक्रॉन नाम का नया वेरिएंट आ गया जिससे 2021–22 में आर्थिक वृद्धि की गति धीमी पड़ गई। अन्य वेरिएंट्स की आशंका के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता के दौर से गुज़र रही है।

2.3 वर्ष 2020 और 2021, नोवेल कोरोना वायरस के कारण भारी उथल पुथल के साक्षी बने और यह महामारी किसी एक सदी में आर्थिक वृद्धि के समक्ष सबसे बड़ा संकट बन कर उभरी। अर्थव्यवस्था और समाज के लगभग प्रत्येक हिस्से पर व्यापक असर के कारण यह महामारी एक अभूतपूर्व विपत्ति के रूप में सामने आई। इसका अर्थव्यवस्था की आपूर्ति और मांग, दोनों पक्षों पर भारी असर पड़ा।

2.4 संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए अपनाए गए उपायों का भारी आर्थिक मूल्य चुकाना पड़ा, क्योंकि इनके कारण लगभग पूरी आर्थिक गतिविधियां बंद हो गईं, उपभोग और इन्वेस्टमेंट पर अंकुश लग गया और साथ ही श्रम की आपूर्ति और उत्पादन प्रतिबंधित हुआ। इस प्रकार कोविड–19 ने पूरे विश्व को लोगों का ''जीवन'' और ''आजीविका'' बचाने के कठिन संकट में डाल दिया, क्योंकि संक्रमण की वक्र रेखा को समतल करने के लिए उठाए गए कदमों ने वृहद आर्थिक मंदी की वक्र रेखा और गहरी कर दी।

2.5 ये महामारी एक जबरदस्त आर्थिक आघात के रूप में सामने आई, जिसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की आपूर्ति और मांग पक्ष दोनों को आघात पहुंचाया। बढ़ती हुई अनिश्चितता, कम होता भरोसा, आय में कमी, विकास की दुर्बल संभावनाएं, संक्रमण का भय, सभी प्रकार की संपर्क संवेदनशील गतिविधियों के बंद हो जाने के कारण व्यय विकल्पों में कमी, एहतियातन बचत करने की विवशता, व्यवसायों के बंद होने का जोखिम और इसके कारण उपभोग और निवेश में गिरावट से मांग पक्ष को भारी आघात पहुंचा। आर्थिक गतिविधियों के बंद हो जाने और श्रमिकों की आवाजाही पर पाबंदी से आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ा। आपूर्ति पक्ष में पहले क्रम के व्यवधान ने मांग और आपूर्ति, दोनों पर दूसरे दौर का भी नकारात्मक असर डाला। आपूर्ति पर आरंभिक आघात के कारण पारिश्रमिक और आय में कमी आने से आगे भी समग्र मांग पर असर पड़ेगा और उत्पादन क्षमता प्रभावित होगी, जो आगे फिर आपूर्ति को प्रभावित करेगा। टीकाकरण से मृत्यु दर काफी हद तक कम करने में सफलता मिली, आर्थिक, गतिविधियां फिर शुरू करने का हौंसला और दूसरी लहर से आई आर्थिक मंदी से उत्पादन में आई कमी रोकने में मदद मिली।

2.6 दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (मौजूदा मूल्यों पर) में वर्ष 2020–21 के दौरान 1.09 प्रतिशत का संकुचन कोविड महामारी और रोकथाम उपायों के असर को उजागर करता है। अर्थव्यवस्था की अंतर–निहित शक्तियों के आधार पर वर्ष 2021–22 में दिल्ली की वास्तविक जीएसडीपी में 10.23 प्रतिशत की वृद्धि में वापसी की आशा है। दिल्ली में जीएसवीए/जीएसडीपी के स्तर में राष्ट्रीय जीवीए/जीडीपी के मुकाबले वृद्धि हुई है जो विवरण–2.1 में दर्शाई गई है।

विवरण 2.1
अर्थव्यवस्था की वृद्धि और क्षेत्रवार सुधार (स्थिर मूल्यों पर)

क्र स	क्षेत्र	पिछले वर्षों के मुकाबले वृद्धि						सुधार वर्ष 2019-20	
		2019-20		2020-21		2021-22			
		दिल्ली	अखिल भारत	दिल्ली	अखिल भारत	दिल्ली	अखिल भारत	दिल्ली	अखिल भारत
1	कृषि, वानिकी और मछली पालन	-0.74	5.5	-17.36	3.3	-2.85	3.3	80.29	106.70
2	खनन और खुदाई	9.46	-1.5	9.68	-8.6	10.66	12.6	121.37	102.85
3	विनिर्माण	5.56	-2.9	-0.42	-0.6	29.91	10.5	129.37	109.81
4	बिजली, गैस, जल सप्लाई और अन्य सुविधा सेवाएं	-1.74	2.2	15.63	-3.6	11.41	7.8	128.82	103.85
5	निर्माण	-3.19	1.2	-6.45	-7.3	25.91	10.0	117.79	101.92
6	व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारण से जुड़ी सेवाएं	5.93	5.9	-19.77	-20.2	10.54	11.6	88.68	89.14
7	वित्तीय, जायदाद (संपत्ति), और पेशेवर सेवाएं	4.51	6.7	3.07	2.2	4.45	4.3	107.66	106.64
8	जन प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	9.12	6.3	-2.00	-5.5	8.06	12.5	105.89	106.35
	जीएसवीए/जीवीए बुनियादी मूल्यों पर	**5.17**	**3.8**	**-4.34**	**-4.8**	**9.26**	**8.3**	**104.51**	**103.07**
	जीएसवीए/जीडीपी बाजार मूल्यों पर	**3.89**	**3.7**	**-3.86**	**-6.6**	**10.23**	**8.9**	**105.98**	**101.76**

2.7 बड़े पैमाने पर सफल टीकाकरण अभियान से अर्थव्यवस्था की स्थिति वापिस सामान्य होने लगी है और सेवा क्षेत्र खपत और निवेश में तेजी से सुधार के आसार बन गए हैं। कुल मिलाकर दिल्ली की आर्थिक गतिविधि राष्ट्रीय स्थिति के मुकाबले अधिक तेजी से सुधर रही है। वर्ष 2021–22 में दिल्ली की वास्तविक जीसडीपी लगभग 10 प्रतिशत को पार कर जाने की आशा है।

3. प्रचलित मूल्यों पर आकलन

वर्ष 2019–20 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 794030 करोड़ रुपये आंका गया था, जो इससे पहले के वर्ष के मुकाबले 7.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता था। वर्ष 2020–21 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली का जीएसडीपी, 1.09 प्रतिशत की गिरावट के साथ, 785342 करोड़ रुपये हो गया। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान दिल्ली के जीएसडीपी के अग्रिम आकलन में इसके 923967 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंचने की संभावना है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 17.65 प्रतिशत अधिक है। दिल्ली का निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) प्रचलित मूल्यों पर 2019–20 के दौरान 713549 करोड़ रुपये आंका गया था, जिसमें इससे पहले के वर्ष के मुकाबले 7.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्ष 2020–21 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली का एनएसडीपी घट् कर 702519 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 1.55 प्रतिशत की कमी रही। वर्ष 2021–22 के दौरान दिल्ली के एनएसडीपी के अग्रिम आकलन के 836162 करोड़ रुपये के स्तर पर आने की संभावना है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 19.02 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

3.1 इससे पता चलता है कि कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में सुधार आने लगा है।

3.2 अधिकांश शहरी अर्थव्यवस्था में हुई सामान्य प्रक्रिया की भांति ही दिल्ली में सेवा क्षेत्र में बढ़ोत्तरी का रुझान है। वर्तमान मूल्यों पर दिल्ली के सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन (जीएसवीए) के प्रतिशत वितरण से पता चला है कि कुछ वर्षों में मामूली उतार–चढ़ाव के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में गिरावट का रुख है जबकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में मिलाजुला रुख रहा। खासकर दिल्ली में जीएसवीए के प्राथमिक क्षेत्र के प्रतिशत योगदान वर्तमान मूल्यों पर 2011–12 के 3.49 प्रतिशत से घटकर 2021–22 में 2.28 प्रतिशत रह गया। इसी अवधि में जीएसवीए में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान वर्तमान मूल्यों पर 13.09 प्रतिशत से बढ़कर 13.78 प्रतिशत हो गया जबकि तृतीयक (सेवा) क्षेत्र का जीएसवीए में योगदान वर्तमान मूल्यों पर 2011–12 के 83.42 प्रतिशत से बढ़कर 2021–22 में 83.94 प्रतिशत हो गया।

4. स्थिर मूल्यों पर आकलन (आधार वर्ष 2011–12)

4.1 दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2019–20 के दौरान 587316 करोड़ रुपये रिकार्ड किया गया था, जिसमें उससे पिछले वर्ष की तुलना में 3.89 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई। 2020–21 के दौरान स्थिर मूल्यों पर दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद घटकर 564669 करोड़ रुपये रह गया, जिसमें 3.86 प्रतिशत की कमी रही। 2021–22 के दौरान दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद अग्रिम आकलन के अनुसार यह स्थिर मूल्यों पर 622430 करोड़ रुपये रिकॉर्ड किया गया, जिसमें 2019–20 की तुलना में 10.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2019–20 के

दौरान स्थिर मूल्यों पर दिल्ली का निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) 521994 करोड़ रुपये आंका गया था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 3.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। 2020–21 के दौरान स्थिर मूल्यों पर दिल्ली का निवल राज्य घरेलू उत्पाद घटकर 496284 करोड़ रुपये आंका गया है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 4.93 प्रतिशत की कमी रही। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान स्थिर मूल्यों पर दिल्ली के एनएसडीपी का अग्रिम आकलन 548058 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 2020–21 की तुलना में 10.43 प्रतिशत विकास की संभावना है।

4.2 2011–12 के मूल्यों पर दिल्ली के सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन (जीएसवीए) में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में मामूली बदलाव को छोड़कर गिरावट का रुख रहा लेकिन द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में मिलाजुला रुख रहा। दिल्ली के जीएसवीए में 2011–12 के मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र का प्रतिशत योगदान 3.49 से घटकर 2021–22 में 3.08 प्रतिशत रह गया। इसी अवधि में स्थिर मूल्यों पर दिल्ली के द्वितीयक क्षेत्र का योगदान बढ़कर 13.09 प्रतिशत से 15.52 प्रतिशत हो गया। दिल्ली के जीएसवीए में 2011–12 के मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का योगदान 83.42 प्रतिशत से घटकर 2021–22 में 81.40 प्रतिशत रह गया।

4.3 प्रचलित मूल्यों और 2011–12 के मूल्यों के आधार पर पिछले 11 वर्षों में दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में जानकारी विवरण 2.2 में दी गयी है।

विवरण 2.2

प्रचलित और 2011–12 के मूल्यों पर दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रुपये)

क्र.स	वर्ष	बाजार मूल्यों पर जीएसडीपी		बाजार मूल्यों पर एनएसडीपी	
		प्रचलित	स्थिर (2011–12)	प्रचलित	स्थिर (2011–12)
1.	2011-12	343798	343798	314650	314650
2.	2012-13	391388	366628	357400	334193
3.	2013-14	443960	392908	404841	356528
4.	2014-15	494803	428355	448487	387639
5.	2015-16	550804	475623	500524	431730
6.	2016-17	616085	511765	558546	461592
7.	2017-18	677900	542015	613631	487631
8.	2018-19 (तृ.सं.अ)	738389	565327	665808	506332
9.	2019-20 (द्वि.सं.अ)	794030	587316	713549	521994
10.	2020-21 (प्र.सं.अ)	785342	564669	702519	496284
11.	2021-22 (अ.आ.)	923967	622430	836162	548058

स्रोत : अर्थ और सांख्यिकीय निदेशालय, राराक्षे, दिल्ली सरकार

नोट : (तृ.सं.अ)–तृतीय संशोधित आकलन, (द्वि.सं.अ)–द्वितीय संशोधित आकलन, (प्र.स.अ.)–प्रथम संशोधित आकलन, (अ.अ.)– अग्रिम आकलन

4.4 प्रचलित और स्थिर मूल्यों (2011–12) पर दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) चार्ट 2.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1

दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद– प्रचलित और स्थिर मूल्यों पर

(करोड़ रुपये)

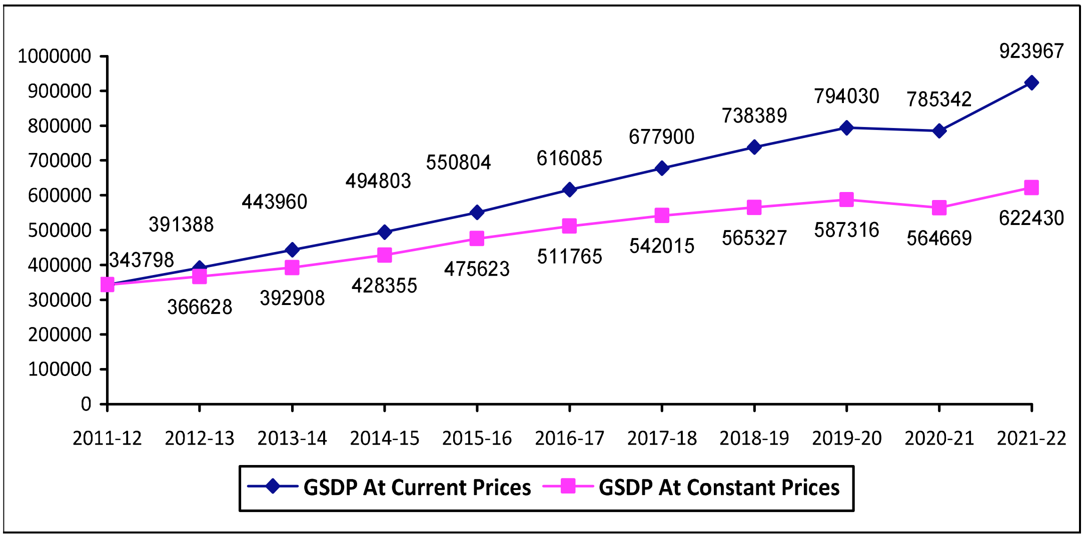

4.5 पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रचलित और 2011–12 के मूल्यों पर दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत वृद्धि विवरण 2.3 में दी गयी है।

विवरण 2.3

प्रचलित और स्थिर मूल्यों पर दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि

(प्रतिशत में)

क्र. स.	वर्ष	जीएसडीपी बाजार मूल्य पर		एनएसडीपी बाजार मूल्य पर	
		प्रचलित	स्थिर (2011–12)	प्रचलित	स्थिर (2011–12)
1.	2012-13	13.84	6.64	13.59	6.21
2.	2013-14	13.43	7.17	13.27	6.68
3.	2014-15	11.45	9.02	10.78	8.73
4.	2015-16	11.32	11.03	11.60	11.37
5.	2016-17	11.85	7.60	11.59	6.92
6.	2017-18	10.03	5.91	9.86	5.64
7.	2018-19	8.92	4.30	8.50	3.84
8.	2019-20	7.54	3.89	7.17	3.09
9.	2020-21	-1.09	-3.86	-1.55	-4.93
10.	2021-22	17.65	10.23	19.02	10.43

स्रोत : अर्थ और सांख्यिकीय निदेशालय, राराक्षे, दिल्ली सरकार

4.6 राज्य घरेलू उत्पाद के आकलन की संक्षिप्त पद्धति

4.6.1 अर्थव्यवस्था का **प्राथमिक क्षेत्र** धरती से उत्पादों का निष्कर्षण अथवा अर्जन करता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कच्चे माल और बुनियादी खाद्यान्न का उत्पादन शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र से सम्बद्ध गतिविधियों में कृषि (आजीविका और वाणिज्यिक दोनों), खनन, वानिकी, खेती, चारागाह, शिकार और संग्रहण, मत्स्य उद्योग और खनन एवं उत्खनन शामिल हैं। इस क्षेत्र से सम्बद्ध कच्चे माल की पैकेजिंग और प्रसंस्करण को भी इस क्षेत्र का हिस्सा समझा जाता है। कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग के लिए जीएसवीए के अनुमान सरकारी सिंचाई प्रणाली के प्रचालन को छोड़ कर उत्पादन पद्धति से संकलित किए जाते हैं, जिसके लिए आय पद्धति अपनाई जाती है। खनन और उत्खनन उद्योग में जीएसवीए के अनुमान गैर–विभागीय उद्यम और निजी कार्पोरेट उद्यमों से सम्बद्ध कंपनियों के वार्षिक वित्तीय ब्यौरों से संकलित किए जाते हैं। कंपनियों के ये ब्यौरे एमसीए 21 डेटाबेस से निकाले जाते हैं।

4.6.2 अर्थव्यवस्था के **द्वितीयक क्षेत्र** के अंतर्गत ऐसे आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं, जो उपभोग के लिए तैयार, इस्तेमाल योग्य उत्पाद बनाते हैं; जिनमें विनिर्माण, निर्माण और विद्युत, गैस और जलापूर्ति और उपयोग संबंधी अन्य सेवाएं शामिल हैं। यह क्षेत्र आमतौर पर प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों से तैयार वस्तुओं का विनिर्माण करता है, या ऐसी वस्तुएं बनाता है, जो अन्य व्यवसायों द्वारा निर्यात, या घरेलू उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस क्षेत्र के जीएसवीए के आकलन के लिए, समूची विनिर्माण गतिविधियों को मोटेतौर पर दो व्यापक खंडों में वर्गीकृत किया जाता है, ये हैं – विनिर्माण –'संगठित विनिर्माण' और 'असंगठित विनिर्माण'। संगठित विनिर्माण क्षेत्र के लिए अनुमानों के वास्ते गैर–विभागीय उद्यमों (एनडीई) के वार्षिक खातों, निजी कॉर्पोरेट सेक्टर के मामले में एमसीए डेटा बेस और अर्द्ध–निगमों के मामले में वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एएसआई) के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। असंगठित विनिर्माण के अंतर्गत घरेलू उद्यम शामिल हैं। गैर–निगमित विनिर्माण उद्यमों के सकल मूल्य संवर्धन के श्रेणीवार आकलन संकलन के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 67वें दौर (गैर–निगमित उद्यम संबंधी) के सर्वेक्षण, 2011–12 और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 68वें दौर (रोजगार बेरोजगारी संबंधी) के सर्वेक्षण, 2011–12 के लिए प्रभावकारी श्रम लागत पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। विद्युत सब–क्षेत्र में जीएसवीए के आकलन आय पद्धति का इस्तेमाल करते हुए तैयार किए जाते हैं। ये आकलन राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य में स्थित अन्य विद्युत प्रतिष्ठानों के वार्षिक लेखों के विश्लेषण के आधार पर लगाए जाते हैं। गैस के संदर्भ में जीएसवीए के अनुमान उद्यमिता दृष्टिकोण के जरिए संकलित किए जाते हैं। जलापूर्ति के लिए जीएसवीए के आकलन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए अलग अलग आय पद्धति के आधार पर संकलित किए जाते हैं। उपचार और अन्य जनोपयोगी सेवाओं के लिए जीएसवीए के आकलन रीसाइकलिंग, री–मेडिएशन, सीवरेज और अन्य कचरा प्रबंधन सेवाओं की समग्र रूप में गणना करते हुए संकलित किए जाते हैं। समूची अर्थव्यवस्था के लिए लेखाबद्ध निर्माण के आकलन पहले वस्तु आपूर्ति दृष्टिकोण से लगाए जाते हैं। निजी निगमों के बारे में आकलन कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा गैर–सरकारी कंपनियों के वित्तीय मानदंड के बारे में एमसीए–21 डेटा बेस द्वारा प्रदत्त जानकारी का इस्तेमाल करते हुए किए जाते हैं।

4.6.3 **तृतीयक क्षेत्र** की दिल्ली के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है और यह रोजगार क्षमता और राज्य की आय में योगदान, दोनों ही संदर्भों में अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग है। यह क्षेत्र व्यापक गतिविधियों को कवर करता है, जिनमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जैसे सर्वाधिक अत्याधुनिक क्षेत्र से लेकर असंगठित, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा दी जाने वाली सामान्य सेवाओं तक शामिल हैं, जैसे सब्जी विक्रेता, फेरी वाले, रिक्शा चालक आदि की सेवाएं। औद्योगिक श्रेणी के संदर्भ में, इस क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल और रेस्त्रां; परिवहन; भंडारण; संचार; वित्तीय सेवाएं; रीयल एस्टेट; रिहायशी और व्यावसायिक सेवाओं का स्वामित्व; लोक प्रशासन; और शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जैसी सेवाएं आती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र खंड के लिए जीएसवीए वार्षिक रिपोर्टों/खातों और बजट दस्तावेजों के आर्थिक विश्लेषण के जरिए प्राप्त किया जाता है। प्राइवेट निगमों के आकलन एमसीए–21 डेटा बेस और एनएसएस सर्वेक्षणों के परिणामों का इस्तेमाल करते हुए संकलित किए जाते हैं।

5. प्रति व्यक्ति आय

5.1 प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2020–21 के दौरान 344136 रुपये पहुंच गई, जबकि यह 2019–20 में यह 356151 रुपये और 2018–19 में 338730 रुपये थी। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021–22 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 401982 रुपये पर पहुंचने का अनुमान है। प्रचलित मूल्यों पर पिछले 10 वर्षों (2013–22) में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 11.12 प्रतिशत, 10.86 प्रतिशत, 8.47 प्रतिशत, 9.32 प्रतिशत, 9.36 प्रतिशत, 7.70 प्रतिशत, 6.41 प्रतिशत, 5.14 प्रतिशत (–) 3.37 प्रतिशत और 16.81 प्रतिशत रही है।

5.2 2021–22 में स्थिर मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 243114 रुपये रही जबकि 2019–20 में यह 260541 रुपये थी, अर्थात् इसमें 6.69 प्रतिशत की वार्षिक गिरावट दर्ज हुई। वर्ष 2021–22 में स्थिर मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार इसके 263477 रुपये पर रहने की संभावना है। इस प्रकार इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 8.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

5.3 दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित और स्थिर दोनों ही मूल्यों पर राष्ट्रीय औसत से लगभग तिगुनी थी। पिछले ग्यारह वर्षों में दिल्ली और समग्र भारत की प्रति व्यक्ति आय के बारे में जानकारी विवरण 2.4 में दी गयी है।

विवरण 2.4

2011–12 से 2021–22 के दौरान दिल्ली और भारत की प्रति व्यक्ति आय

(रुपये में)

वर्ष	प्रचलित मूल्य (आधार वर्ष 2011–12)		स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011–12)	
	दिल्ली*	अखिल भारतीय	दिल्ली*	अखिल भारतीय
2011–12	185001	63462	185001	63462
2012–13	205568	70983	192220	65538
2013–14	227900	79118	200702	68572
2014–15	247209	86647	213669	72805
2015–16	270261	94797	233115	77659
2016–17	295558	104880	244255	83003
2017-18	318323	115224	252960	87586
2018-19 (तृ.सं.अ)	338730	125946	257597	92133
2019-20 (द्वि.सं.अ)	356151	132115	260541	94270
2020-21 (प्र.सं.अ)	344136	126855	243110	85110
2021-22 (अ.आ.)	401982	149848	263477	91723

स्रोत : अर्थ और सांख्यिकीय निदेशालय, राराराक्षे, दिल्ली सरकार

नोट : (तृ.सं.अ)–तृतीय संशोधित आकलन, (द्वि.सं.अ)–द्वितीय संशोधित आकलन, (प्र.स.अ.) – प्रथम संशोधित आकलन, (अ.अ.) – अग्रिम आकलन

** राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा तैयार नवीनतम जनसंख्या अनुमानों का उपयोग किया गया है।*

5.4 विवरण 2.4 से यह पता चलता है कि 2011–12 में प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 185001रुपये थी, जो 2021–22 में बढ़कर 401982 रुपये हो गयी, अर्थात् इसमें 8.18 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज हुई। इसी अवधि के दौरान स्थिर मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में 3.69 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोत्तरी हुई। प्रचलित और स्थिर दोनों मूल्यों पर पिछले 11 वर्ष के दौरान दिल्ली और भारत की प्रति व्यक्ति आय संबंधी जानकारी क्रमशः चार्ट 2.2.1 और 2.2.2 में दी गयी है।

5.5 प्रचलित और स्थिर मूल्यों पर दिल्ली और राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर विवरण 2.4 में दी गयी है।

चार्ट 2.2.1

प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली और भारत की प्रति व्यक्ति आय

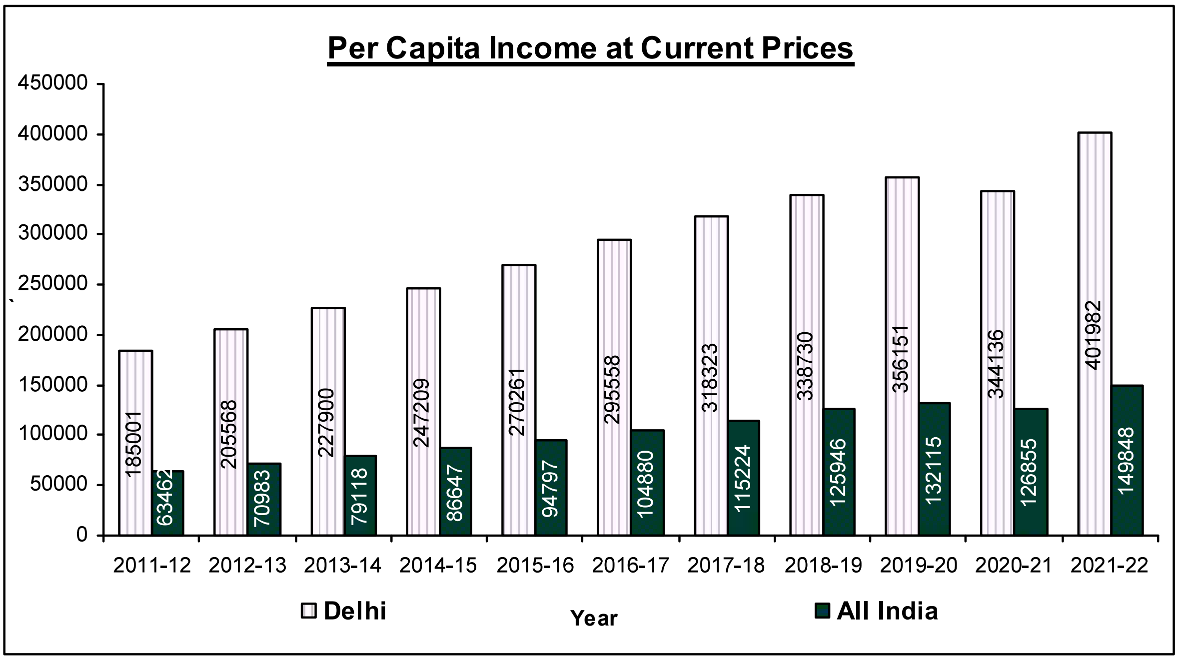

चार्ट 2.2.2

स्थिर मूल्यों पर दिल्ली और भारत की प्रति व्यक्ति आय

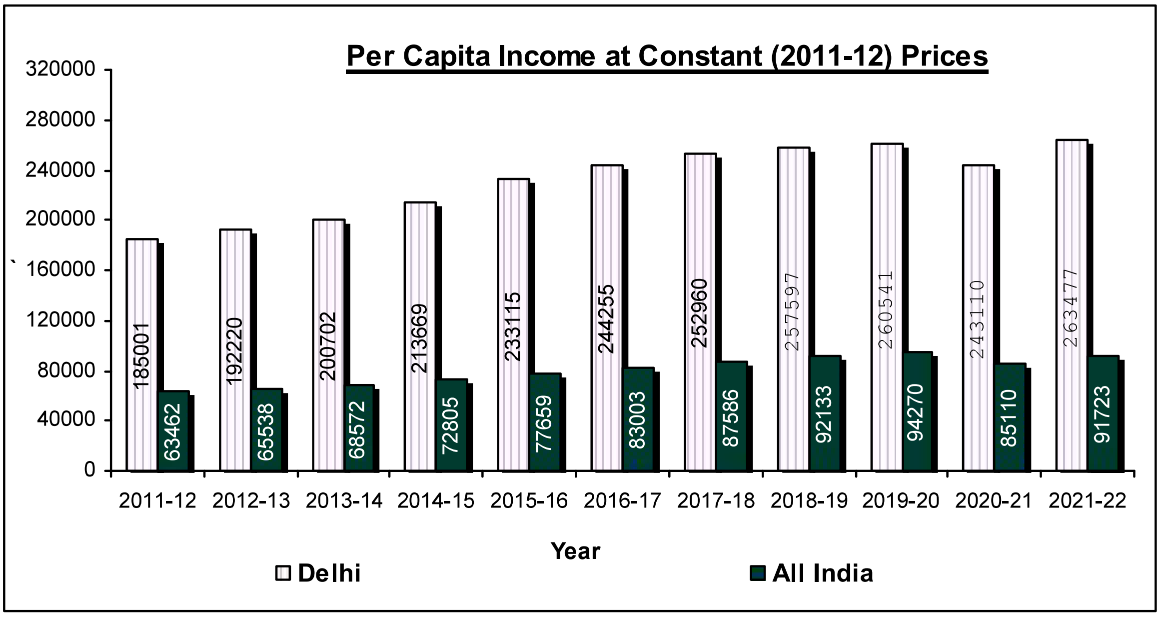

विवरण 2.5

2012–13 से 2021–22 के बीच दिल्ली और भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर

(प्रतिशत)

क्र.स	वर्ष	दिल्ली		भारत	
		प्रचलित	स्थिर (2011-12)	प्रचलित	स्थिर (2011-12)
1.	2012-13	11.12	3.90	11.9	3.3
2.	2013-14	10.86	4.41	11.5	4.6
3.	2014-15	8.47	6.46	9.5	6.2
4.	2015-16	9.32	9.10	9.4	6.7
5.	2016-17	9.36	4.78	10.6	6.9
6.	2017-18	7.70	3.56	9.9	5.5
7.	2018-19	6.41	1.83	9.3	5.2
8.	2019-20	5.14	1.14	4.9	2.3
9.	2020-21	-3.37	-6.69	-4.0	-9.7
10.	2021-22	16.81	8.38	18.1	7.8

स्रोत : अर्थ और सांख्यिकीय निदेशालय, राराक्षे, दिल्ली सरकार

6. सकल राज्य मूल्य संवर्धित (जीएसवीए) की क्षेत्रगत संरचना

6.1 दुनिया की अधिकतर शहरीकृत क्षेत्रों में आम रुझान के अनुरूप दिल्ली की आमदनी में भी प्रमुख योगदान सेवा क्षेत्र का है। सकल राज्य मूल्य संवर्धित (जीएसवीए) में क्षेत्रगत बढ़ोतरी के विशलेषण से भी इसी तथ्य का स्पष्ट पता चलता है। समग्र जीएसवीए में प्राथमिक क्षेत्र (जिसमें कृषि, पशुधन, वानिकी, मछली उद्योग, खनन और उत्खनन शामिल हैं) में पिछले 11 वर्षों में लगातार गिरावट का रुझान रहा है, कुछ गौण विचलों को छोड़कर। द्वितीयक क्षेत्र के योगदान में मिश्रित रुझान रहा है। प्रचलित और स्थिर मूल्यों (2011–12) के संदर्भ में तीन अलग अलग क्षेत्रों, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और सेवा क्षेत्र में दिल्ली के जीएसवीए की संरचना 2011–12 से 2021–22 की अवधि के लिए विवरण 2.6 मे दी गई है।

विवरण 2.6
दिल्ली में जीएसवीए की क्षेत्रगत संरचना (बुनियादी मूल्यों पर) – प्रचलित और स्थिर मूल्यों (2011–12) पर

(करोड़ रुपये)

क्रसं.	वर्ष	प्राथमिक		द्वितीयक		तृतीयक		कुल	
		करोड रुपये	%	करोड रुपये	%	करोड रुपये	%	करोड रुपये	%
1	2011-12								
	क. प्रचलित	10585.42	3.49	39682.08	13.09	252964.99	83.42	303232.49	100.00
	ख. स्थिर	10585.42	3.49	39682.08	13.09	252964.99	83.42	303232.49	100.00
2	2012-13								
	क. प्रचलित	10048.44	2.93	48498.08	14.17	284041.02	82.90	342587.54	100.00
	ख. स्थिर	9061.01	2.82	45118.64	14.06	266752.79	83.12	320932.43	100.00
3	2013-14								
	क. प्रचलित	12741.36	3.29	54262.39	14.07	318927.16	82.64	385930.91	100.00
	ख. स्थिर	10621.54	3.10	47802.34	13.99	283200.89	82.91	341624.77	100.00
4	2014-15								
	क. प्रचलित	12115.29	2.79	53246.72	12.26	368879.09	84.95	434241.10	100.00
	ख. स्थिर	11129.20	2.96	45154.35	12.01	319564.22	85.03	375847.77	100.00
5	2015-16								
	क. प्रचलित	9987.11	2.09	65194.32	13.62	403600.12	84.29	478781.54	100.00
	ख. स्थिर	11534.36	2.80	55107.47	13.41	344275.62	83.79	410917.45	100.00
6	2016-17								
	क. प्रचलित	9008.82	1.70	71615.66	13.48	450550.91	84.82	531175.39	100.00
	ख. स्थिर	10611.73	2.42	58147.77	13.28	369230.31	84.30	437989.81	100.00
7	2017-18								
	क. प्रचलित	9776.09	1.67	80986.80	13.80	496136.82	84.53	586899.72	100.00
	ख. स्थिर	11269.34	2.43	63186.70	13.65	388876.89	83.92	463332.93	100.00
8	2018-19								
	क. प्रचलित	13482.10	2.08	87160.20	13.45	547196.76	84.47	647839.05	100.00
	ख. स्थिर	13235.04	2.71	65940.96	13.49	409406.47	83.80	488582.47	100.00
9	2019-20								
	क. प्रचलित	13704.04	1.94	88887.04	12.58	603971.28	85.48	706562.36	100.00
	ख. स्थिर	14287.14	2.78	66478.06	12.95	433084.37	84.27	513849.57	100.00
10	2020-21								
	क. प्रचलित	12337.39	1.77	89364.10	12.85	594016.35	85.38	695717.83	100.00
	ख. स्थिर	15144.55	3.08	67355.83	13.70	409051.30	83.22	491551.68	100.00
11	2021-22								
	क. प्रचलित	18405.05	2.28	111541.03	13.78	679404.18	83.94	809350.27	100.00
	ख. स्थिर	16541.33	3.08	83378.83	15.52	437125.93	81.40	537046.09	100.00

स्रोत : अर्थ और सांख्यिकीय निदेशालय, राराराक्षे, दिल्ली सरकार।
राउंडिंग ऑफ के कारण संभव है कि जोड़ का मिलान न हो

6.2 विवरण 2.5 से पता चलता है कि 2011–12 में दिल्ली की आय में 82 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र की है, 15 प्रतिशत से कम द्वितीयक क्षेत्र की और चार प्रतिशत से भी कम प्राथमिक क्षेत्र की रही है। अधिक स्पष्ट रूप में कहें तो 2011–12 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 3.49 प्रतिशत था जो 2021–22 में घटकर 2.28 प्रतिशत रह गया। इसके विपरीत तृतीयक क्षेत्र का योगदान 2011–12 में प्रचलित मूल्यों पर 83.42 प्रतिशत था जो 2021–22 में बढ़कर 83.94 प्रतिशत हो गया। दिल्ली की आय में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 2011–12 में 13.09 प्रतिशत था जो 2021–22 में बढ़कर 13.78 प्रतिशत हो गया।

6.3 वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान प्रचलित मूल्यों और स्थिर मूल्यों (2011–12) पर दिल्ली के सकल राज्य मूल्य संवर्धित की क्षेत्रगत संरचना चार्ट 2.3 में दर्शायी गयी है।

चार्ट 2.3

प्रचलित और स्थिर मूल्यों (2011–12) पर दिल्ली के जीएसवीए की क्षेत्रगत संरचना

(प्रतिशत में)

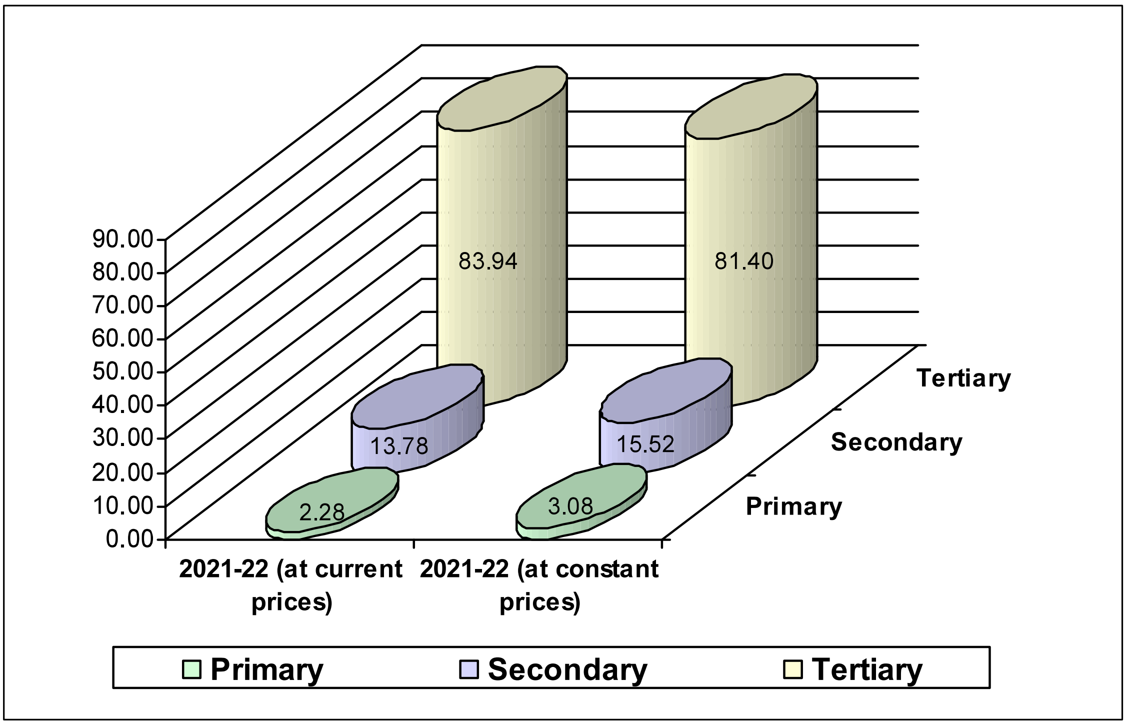

6.4 दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित अन्य सांख्यिकीय जानकारी तालिका 2.1 से तालिका 2.4 के अंतर्गत दी गयी हैं।